

નગર નિગમને ફાઁગિંગ વલાર્વિસાઇડલ સ્પે અભિયાન કિયા શરૂ

નગર આયુક્ત નમામિ બંસલ વ સહાયક નગર આયુક્ત ચૌહાન ને કિયા રેસકોર્સ કા નિરીક્ષણ

મુખ્ય સંવાદદાતા શાહ ટાઇમ્સ દેહારાદૂન નગર નિગમ ને મચ્છરોને સે ઉત્પન્ન બીજારિયાં ડેંગ, મલેરિયા, ચિકન્ગુનિયા એવં અન્ય સંક્રામક રોગોની કોણે રોકથામ કે લિએ એક વિશેષ સંઘર્ષ અભિયાન કોઈ હૈ। નગર આયુક્ત નમામિ બંસલ ને બાબાના કિ યથ અભિયાન નગર નિગમ કે સંખી 100 વાડ્ઝી મેં વ્યવસ્થિત એવ ચર્ચાંડ ઢાંગ સે ચલાયા જા રહ્યો હૈ। નગર નિગમ કા તુલેશ્ય હૈ કિ શહરવાસીઓ કો એવ સ્વચ્છ, સ્વસ્થ એવ સુધીના વાતાવરણ ઉપલબ્ધ કરાયા જાએ ઔર બરસાત કે મોસમ મેં મચ્છરોને સે હોને વાલે સંક્રામકોનો કો નિરીક્ષણ કિયા જા સકે જિસકે લિએ એવ નગર આયુક્ત નમામિ બંસલ ને અભિયાન કે અંતર્ગત બધ્વરાવ કો રોકસર્સ મેં નિરીક્ષણ કિયા, જિસમેં વાડ્ઝી મેં પાર્સિં રોહન ચર્ચેલ ઔર કીર્દેચ બિન્ટ, સહાયક નગર આયુક્ત



રાજીબોર સિંહ ચૌહાન, મુખ્ય સફાઈ નિરીક્ષક નમામિ બંસલ, સફાઈ નિરીક્ષક રાજેશ વહુગુણા આરિ ઉપસ્થિત હોય હૈએ ઇસકે અલાવા કુછ મુખ્ય વિન્બાંઓ પર ભી ચર્ચા કો ગઈ। નગર આયુક્ત નમામિ બંસલ ને બાબાના

निशाने पर पीएम-सीएम

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में एक बिल पेश किया है, जिसमें गिरफतारी या 30 दिन हिरासत पर पीएम-सीएम का पद समाप्त हो जाएगा। यह 5 साल से अधिक सजा वाले अपराध में लागू होगा। सरकार ने इस बिल को जेपीसी को भेज दिया है, वहीं विपक्ष ने विरोध किया है। जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश किया, तो विपक्षी सदस्यों ने बेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया।

विपक्ष का तर्क है कि इस बिल के बहाने मोदी सरकार देश की न्याय व्यवस्था को कमज़ोर करना चाह रही है, जिसे वे नहीं होने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इससे संबंधित तीव्र बिल पेश किए। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। ये तीनों बिल अलग-अलग इसलिए लाए गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। विपक्ष ने इस बिल को महा-आपातकाल से भी बढ़कर बताया और कहा कि यह भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला कहसू है। यह कठोर कहसू में लोकतंत्र और संघवाद के लिए मृत्यु-घंटी है। अधिकार इस बिल में ऐसा क्या है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है।

केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 के तहत गंभीर आपाधिक आरोपों के कारण गिरफतार और हिरासत में लिए गए सीएम या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 45 में संशोधन करने की जरूरत है। वहीं संविधान विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार, संविधान के तहत गंभीर आपाधिक आरोपों में गिरफतार और हिरासत में लिए गए मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239ए में संशोधन की जरूरत है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत गंभीर आपाधिक आरोपों के कारण गिरफतार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 45 में संशोधन करने की जरूरत है। वहीं संविधान विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार, संविधान के तहत गंभीर आपाधिक आरोपों में गिरफतार और हिरासत में लिए गए मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239ए में संशोधन की जरूरत है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत गंभीर आपाधिक आरोपों के कारण गिरफतार और हिरासत में लिए गए सीएम या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 45 में संशोधन करने की जरूरत है। वहीं संविधान विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार, संविधान के तहत गंभीर आपाधिक आरोपों में गिरफतार और हिरासत में लिए गए मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239ए में संशोधन की जरूरत है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन की जरूरत है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे बिलों की आड़ में सरकार संविधान बदलना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा।

पुलिस स्टेट बन जाएगा देश

संविधान संसोधन विधेयक में निहित शक्ति-विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है और जनता के जरिये चुनी हुई सरकारों के अधिकार को कमज़ोर करता है, इसका कार्यकारी विभाजन को खुलौ छूट मिल जाएगा कि वे मामूली आरोपों और शक के आधार पर ही जज और जल्लाद दोनों बन जाएं, यह सरकार किसी भी कीमत पर देश को पुलिस स्टेट में बदलने पर तुली हुई है, यह कहसू हुई सरकारों पर सीधा हमला है और लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करने वाला है, अगर इन विधेयकों को लागू किया गया, तो यह भारत के लोकतंत्र पर डंथ नेत (अंतिम वर्त) सांवित होगा।

-असद हीन ओवैसी
सांसद, एआईएमआईएम

टे

श की सियासत बहुत तेजी से करवते बदल रही है साथ ही जननायक की भूमिका में आकर्षणीय के नेता राहुल गांधी की बैकोवारी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी की सियासी गुणीता में मोदी की भाजपा सहित एनडीए भी फैसला दिखाइ दे रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का मुकाबला रोचक हो गया है, क्योंकि यह चुनाव दिखाया करता है वो नेताओं के बीच होने की सभावना बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति में बड़ा धमाका हो चुका है।

एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को हराने के लिए नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी ने मोदी स्ट्रोक में ही मास्टर स्ट्रोक के चुनाव का मुकाबला रोचक हो गया है। सरकार ने इस बिल को जेपीसी को भेज दिया है, वहीं विपक्ष ने विरोध किया है। जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश किया, तो विपक्षी सदस्यों ने बेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया।

विपक्ष का तर्क है कि इस बिल के बहाने मोदी सरकार

जननायक राहुल गांधी का एक दांव और एनडीए की घड़कने तेज



तकलीफ कुरैशी

क्या नरेन्द्र मोदी को इस बात खतरा था कि कहीं आएरसाएस खेला ना कर दे वहाँ एनडीए के संसदीय नेताओं को बैठक में ही नरेन्द्र मोदी ने अपने नाम पर मुद्र लगवाई थी क्या नरेन्द्र मोदी और आरएसएस के बीच चल ही रस्सकशी बचह तो नहीं थी। अगर थी तो क्या अब वह सियासी चिंगारी भड़की या बैसे ही फुसफुसा का ही रह जाएगा जैसे 2024 में रह गई थी क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के एनडीए प्रत्याशी संघ की पृष्ठभूमि से ही आते हैं। यह दांव सिफ

उपराष्ट्रपति चुनाव का नहीं है, वहाँ एनडीए की एक जुटत की असली परीक्षा है। हो सकता है कि

एनडीए की पहली बड़ी दरार इसी चुनाव में खुलकर

सामने आ जाए। अगर यह आशंका सही बनती हुई तो नरेन्द्र मोदी सरकार के सामने भी संकट खड़ा दिखाई देगा और इस संकट से निपटना मुश्किल हो सकता है, तो सावल यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू, जान माहन रेडी और तेलंगाना के केसीआर पार्टी लालन पर चलेंगे या फिर अपने ही राज्य की जमीन से उठे उम्मीदवार के खिलाफ जाकर अपनी राजनीति की सियासी कब्र खोंदेंगे और अगर ऐसा होता है, तो क्या एनडीए की मजबूती सिफर नाम की रह जाएगी?

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

मलेरिया रोकथाम के दो नए प्रयास

म

लेरिया रोकथाम के दो नए प्रयास सामने आए हैं। एक उपाय में इसनीने खनों के बैठक में ही नरेन्द्र मोदी ने अपने नाम पर मुद्र लगवाई थी क्या नरेन्द्र मोदी और आरएसएस के बीच चल ही रस्सकशी बचह करते हुए अब वह सत्त्वार के बीच चल रहा है। जैसे जनता नहीं रही रही अपनी भूमिका दिखाते हुए थीं। अगर थी तो क्या अब वह सियासी चिंगारी भड़की या बैसे ही फुसफुसा करते हुए जब उसने रेडी को उम्मीदवार बनाया है, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से यानी दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका की रखती है। यह दोनों प्रयासों के बीच चल रहा है।

पहले उपाय में आइवरमेक्टिन नामक एक दवा का प्रयोग करता है। यह दवा न केवल कमीयों को मारती है बल्कि जूँ जैसे कीटों की खाली करती है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति इसे गोली के रूप में लेता है, तो उसका खनों के बीच चल ही रस्सकशी बचह करते हुए अब वह सत्त्वार के बीच चल रहा है। यह दवा नहीं है इसके बीच चल ही रस्सकशी बचह करते हुए अब वह सत्त्वार के बीच चल रहा है।

प्रयोगशाला परीक्षण के नीतीजे काफी उत्साहजनक रहे। एक दिन पहले आइवरमेक्टिन लेने वाले लोगों के खनों पर प्रयोग एसें व्यक्ति को काटें जिसने हाल ही में आइवरमेक्टिन ली हो, तो क्या वे भी मर जाएंगे? और अगर एक प्रयोगशाला परीक्षण के नीतीजे काटें जिसने हाल ही में आइवरमेक्टिन ली हो, तो क्या वे भी क्युली और खुलौ दी जाएंगे?

एक दिन पहले आइवरमेक्टिन लेने वाले लोगों के खनों पर प्रयोग एसें व्यक्ति को काटें जिसने हाल ही में आइवरमेक्टिन ली हो, तो क्या वे भी मर जाएंगे? और अगर एक प्रयोगशाला परीक्षण के नीतीजे काटें जिसने हाल ही में आइवरमेक्टिन ली हो, तो क्या वे भी क्युली और खुलौ दी जाएंगे?

प्रयोगशाला परीक्षण के नीतीजे काटें जिसने हाल ही में आइवरमेक्टिन ली हो, तो क्या वे भी मर जाएंगे?

प्रयोगशाला परीक्षण के नीतीजे काटें जिसने हाल ही में आइवरमेक्टिन ली हो, तो क्या वे भी क्युली और खुलौ दी जाएंगे?

प्रयोगशाला परीक्षण के नीतीजे काटें जिसने हाल ही में आइवरमेक्टिन ली हो, तो क्या वे भी मर जाएंगे?

प्रयोगशाला परीक्षण के नीतीजे काटें जिसने हाल ही में आइवरमेक्टिन ली हो, तो क्या वे भी क्युली और खुलौ दी जाएंगे?

